BENNETT, COLEMAN & CO. LTD.

# THE ECONOMIC TIMES

www.et.nbt.in

नवभारत टाइम्स। एनसीआर। शुक्रवार 7 फरवरी 2020

THE ECONOMIC TIMES नई दिल्ली शुक्रवार

# रेपो रेट को लेकर छाई मायूसी, लेकिन स्कीमों से इंडस्ट्री में उत्साह

## CRR और लोन रिस्ट्रक्चरिंग में RBI के ढील देने से लौटेगी रियल एस्टेट में ग्रोथ

[ ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली ]

**इकनॉमिक ग्रोथ** को मोहताज सभी सेक्टरों ने आरबीआई की ओर से पॉलिसी दरों में लगातार दूसरी बार कोई कटौती नहीं होने से निराशा जताई है, लेकिन ऑटो, रियल्टी और एमएसएमई सेक्टर में रिटेल लोन को बढ़ावा देने और प्रोजेक्ट लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की मियाद एक साल बढ़ाने का स्वागत किया है। रियल्टर्स ने उम्मीद जताई है कि आरबीआई के रुख से रिटेल लोन और प्रोजेक्ट कंप्लीशन में तेजी आएगी।

एसोचैम और नारडेको के प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि आर्थिक सुस्ती के बीच फरवरी से दिसंबर 2019 तक 1.35% की कटौती के बाद लगातार दो समीक्षा में रेपो रेट यथावत रखना चौंकाने वाला है। अगर कटौती हुई होती तो सभी सेक्टरों में डिमांड बढ़ाने में मदद मिलती। लेकिन हमें उम्मीद है कि इकनॉमिक सिस्टम में क्रेडिट सप्लाई बढ़ाने के लिए उठाए गए दूसरे कदम कारगर होंगे।

ऐनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर को रिटेल लोन के लिए प्रोविजिनिंग में ढील से बिल्डर्स के साथ ही रिटेल बायर्स को फायदा होगा और डिमांड बढ़ाने में मदद मिलेगी। तंग लिक्विडिटी के बीच यह राहत भरा कदम है। प्रोजेक्ट लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक साल की मोहलत भी राहत भरा कदम है और इससे प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर आएंगे। क्रेडाई अफोर्डेबल

**रेपो रेट में लगातार दूसरी बार कटौती नहीं होने से सभी सेक्टरों ने जताई निराशा**

हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन मनोज गौड़ ने कहा कि कैश रिजर्व रेशियो के लिए बैंकों को नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज में से कई सेक्टरों को दिए जाने वाले इंक्रीमेंटल लोन को घटाने की छूट से रियल एस्टेट को भी काफी फायदा मिलेगा। इससे होम लोन और प्रोजेक्ट लोन दोनों का दायरा बढ़ेगा और ग्रोथ लौटेगी।

हाउसिंग डॉट कॉम के सीईओ ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि रेपो रेट में कटौती नहीं होना बहुत हद तक अपेक्षित है, लेकिन सीआरआर की गणना में खास सेक्टरों के लिए ढील उत्साहजनक है। इससे डिमांड और ग्रोथ दोनों को सहारा मिलेगा। सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में जिस तरह उठान के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में एक कटौती ग्रोथ को ताकत देती, लेकिन अन्य नीतिगत हस्तक्षेप से भी डिमांड बढ़ाने की कोशिश का हम स्वागत करते हैं। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन रवि सहगल ने कहा कि प्रोडक्टिव सेक्टरों के लिए बैंकों को सीआरआर में ढील से एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसका एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। जेएलएल के सीईओ रमेश नायर ने कहा कि प्रमोटर्स के नियंत्रण से बाहर की वजहों के चलते लोन चुकाने में हुई देरी पर एक साल के लिए बढ़ाई गई रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा एक बड़ी राहत है।

क्रेडाई अफोर्डेबल
हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन मनोज गौड़ ने कहा कि कैश रिजर्व रेशियो के लिए बैंकों को नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज में से कई सेक्टरों को दिए जाने वाले इंक्रीमेंटल लोन को घटाने की छूट से रियल एस्टेट को भी काफी फायदा मिलेगा। इससे होम लोन और प्रोजेक्ट लोन दोनों का दायरा बढ़ेगा और ग्रोथ लौटेगी।